Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding atrocities against Dalits in Bihar.

श्री चिराग कुमार पासवान (जमुई): सर, एक माननीय सांसद होने के नाते मैं भारतीय संघीय ढांचे को भली-भांति समझता हूं और इस बात को जानता हूं कि कई अधिकार केन्द्र सरकार के पास होते हैं, तो कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था यकीनन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। पर, ऐसे में अगर एक राज्य, मैं अपने गृह राज्य की बात कर रहा हूं, मैं बिहार से चुन कर यहां आया हूं, जहां पर आपराधिक गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, हत्याएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएं तो ऐसे में यह संसद खामोश नहीं रह सकती है।

सर, मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं, जहां पर एक के बाद एक ऐसी हत्याओं की श्रृंखला शुरू हुई है, जिसमें हर जाति-धर्म के लोग अंकित हैं। भले ही वे व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब, पिछडे वर्ग से संबंधित लोग हों, पर, खासतौर से वहां अनुसूचित जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वहां पर जघन्य अपराध हो रहे हैं। मैं अरवल की घटना का एक उदाहरण देना चाहूंगा। यह पासवान परिवार से संबंधित महिला की बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने तथा न्याय की मांग करने से संबंधित है। प्रशासन भी अपराधियों के साथ मिला हुआ था। रामजी पासवान जी की धर्म पत्नी सुमन देवी अपनी पांच साल की बच्ची के साथ प्रशासन के पास बार-बार न्याय मांगने जाती है, लेकिन प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता है। परिणाम स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता है। उनके घर में पेट्रोल छिड़क कर पांच साल की बच्ची को उसकी मां के साथ जिंदा जला दिया गया। मैं उस बच्ची को अस्पताल में देखने गया था। बच्ची न्याय की उम्मीद रखते हुए पांच-छ: दिनों तक जिंदगी-मौत के साथ लड़ाई लड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया।

एक बेगुसराय की घटना है। वहां एक पासवान महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके अर्धनग्न अवस्था में उनके शरीर को खेत में फेंक दिया गया। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं अपनों को खोने का दर्द जानता हूं। दो साल पहले मैंने अपने पिता जी को खोया था, कल मेरी नानी जी का निधन हो गया, अभी उनके अंतिम संस्कार के 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, इसलिए मैं आज यहां पर कह रहा हूं कि यह बिहारियों का आक्रोश है और राज्य सरकार इस पर पूरी तरह से खामोश है।

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि संसद से उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। इसका स्वत: संज्ञान लेते हुए केन्द्र सरकार इस पर कार्रवाई करे और सीबीआई जांच इन विषयों पर की जाए। धन्यवाद।